

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE - EXTRAORDINARY)  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

No. F.14(9)/LA-2005 | 127

Dated The 30th March, 2005

The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the 29th March, 2005 and is hereby published for general information :-

" THE DELHI APPROPRIATION (NO. 1) ACT, 2005  
(Delhi Act 6 of 2005)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi  
on the 23rd March, 2005)

(29th March, 2005)

AN ACT to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2004-2005.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

**Short title.**

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.1) Act, 2005.

**Issue of**

Rs. 1666,29,67,000/-  
from and out of the  
Consolidated Fund of the  
National Capital Territory  
of Delhi for the financial  
year 2004-2005.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of One thousand six hundred sixty six crores twenty nine lakhs and sixty seven thousand rupees only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2004-2005 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

**Appropriation.**

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said period.

**THE SCHEDULE**  
(See sections 2 and 3)

(Rs. in thousands)

SUMS NOT EXCEEDING				
DEMAND NO.	SERVICES AND PURPOSES	Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2	3	4	5
2	General Administration Revenue	23144	4248	27392
3	Administration of Justice Revenue	78670	18900	97570
4	Finance Revenue	25917	74342	100259
5	Home Revenue	84956	1244	86200
6	Education Revenue	1000	0	1000
	Capital	200	0	200
7	Medical and Public Health Revenue	337402	1064	338466
8	Social Welfare Revenue	1300	200	1500
	Capital	500	0	500
9	Industries Revenue	191408	5282	196690
	Capital	200	0	200
10	Development Revenue	500	1239	1739
	Capital	400	17100	17500
11	Urban Development and Public Works Revenue	2931351	0	2931351
	Capital	8006600	300000	8306600
	Public Debt. Revenue	0	0	0
	Capital	0	4555800	4555800
<b>Total</b>		<b>11683548</b>	<b>4979419</b>	<b>16662967 "</b>

(P.S. Parmar)

Deputy Secretary (Law, Justice & Legislative Affairs)

(दिल्ली राजपत्र - असाधारण भाग 4 में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)

क.सं. एफ.14(9)/विधायी कार्य-2005/127

दिनांक: 30 मार्च, 2005

उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दिनांक 29 मार्च, 2005 को मिली अनुमति के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:-

“ दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, 2005

(2005 का दिल्ली अधिनियम 6)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2005 को यथा पारित  
(29 मार्च, 2005)

वर्ष 2004-2005 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक अधिनियम ।

इसे भारतीय संविधान के 56 वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए।

संक्षिप्त शीर्षक।

(1) इस अधिनियम को विनियोग (संख्या-1) अधिनियम 2004 कहा जाए।

1666,29,67,000/- रुपयों का (2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से वर्ष 2004-2005 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त।

प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए एक हजार छह सौ छियासठ करोड़ उन्ततीस लाख सड़सठ हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2004-2005 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन।

(3) इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

**अनुसूची**  
(खण्ड 2 व 3 देखे)

(रुपये हजारों में)

राशी इससे अधिक नहीं

मांग संख्या	सेवायें एवं उद्देश्य	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधी पर भारित	जोड़	
1	2	3	4	5	
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	23144	4248	27392
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	78670	18900	97570
4	वित्त	राजस्व	25917	74342	100259
5	गृह	राजस्व	84956	1244	86200
6	शिक्षा	राजस्व	1000	0	1000
		पूंजी	200	0	200
7	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	राजस्व	337402	1064	338466
8	समाज कल्याण	राजस्व	1300	200	1500
		पूंजी	500	0	500
9	उद्योग	राजस्व	191408	5282	196690
		पूंजी	200	0	200
10	विकास	राजस्व	500	1239	1739
		पूंजी	400	17100	17500
11	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व	2931351	0	2931351
		पूंजी	8006600	300000	8306600
	सार्वजनिक ऋण	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	4555800	4555800
जोड़		11683548	4979419	16662967	"

(पी.एस. परमार)

उप सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)